भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1903
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

तंजावुर डेल्टा क्षेत्र की कृषि क्षमता के दोहन का प्रस्ताव

1903. श्री मुरसोली एस.:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार का तमिलनाडु के तंजावुर डेल्टा क्षेत्र की कृषि क्षमता को किसी भी केंद्र सरकार की योजनाओं या संस्थाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य संवर्धन को मजबूत करने के लिए दोहन करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल उपरांत हानि कम करने, और निर्यात-उन्मुख प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेल्टा क्षेत्र में ऐसी केंद्रीय सहायता प्राप्त न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): तमिलनाडु में तंजावुर डेल्टा क्षेत्र में अपने समृद्ध कृषि उपज आधार को देखते हुए, मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने की संभावना है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एमओएफपीआई प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से खुदरा विक्रेता तक उत्तम आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्य संवर्धन आदि शामिल हैं। इससे खेती की उपज की बर्बादी कम करने, फसलोत्तर नुकसान को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, प्रसंस्करण स्टार बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एमओएफपीआई ने दिनांक 31.10.2025 तक तमिलनाडु राज्य में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 487.85 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता के साथ 105 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

तमिलनाडु राज्य में दिनांक 31.10.2025 तक पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 17,210 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 387.06 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ मंज़ूरी दी गई है।

अब तक, तमिलनाडु राज्य में दिनांक 31.10.2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत सहायता के लिए 20 स्थानों पर 445.23 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान(निफ्टेम), तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (आईएनआई) है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को हैंडहोल्डिंग सहायता, सलाह, प्रशिक्षण, पायलट प्लांट, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेशन सेवाएं, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान और विकास सहायता, नेटवर्किंग अवसर इत्यादि जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है।

*****